भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3672
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास के प्रमुख घटक

3672. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान बुनियादी शिक्षा , कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य की सुविधा, जो ग्रामीण विकास के प्रमुख घटक हैं, के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बुनियादी शिक्षा , कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के लाभार्थियों की संख्या कम हो गयी है; और
(ग) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2018-19 से स्कूली शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा - एक एकीकृत योजना को कार्यान्वित कर रहा है जो प्री-स्कूली शिक्षा से कक्षा XII तक विस्तारित स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सेवा में रहते प्रशिक्षण , राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षणों का संचालन , अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक विद्यालय को समग्र स्कूल अनुदान , आईसीटी और डिजिटल पहल के लिए सहायता , विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम , शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहल घटक को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को पारंपरिक अनुदेशात्मक शिक्षक-केंद्रित प्रयास से शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण में बदलने के लिए प्रयोग में लाया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए दो कार्यक्रमों अर्थात दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) , जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल , पुनः कौशल और कौशल वृद्धि संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना , स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी पर्याप्त मानव संसाधन, बेहतर उपलब्धता और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित एवं कमजोर समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य समावेशन की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत , आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सक्षम बनाकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 'निःशुल्क निदानात्मक सेवा पहल' कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है जिसका उद्देश्य जन समुदाय के समीप सुलभ और सस्ती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदानात्मक सेवाएं प्रदान करना है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में कमी आती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर निदानात्मक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले रोगियों की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च को कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क दवा सेवा पहल शुरू की है।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों का मूल उद्देश्य देश के सभी पात्र लोगों को बुनियादी शिक्षा , कौशल और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है।

*****